राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 164

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 22 नवंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

जयशंकर बोले, एच-1बी वीजा पर अमेरिका को मनाएगा भारत >>3

सरोकार

कहां गुम हो गई चंपा! ढूंढने निकल पड़ा पूरा भागलपुर

भागलपुर : बिहार की चंपा नदी 1966 में ही प्रदूषण का शिकार हो गई थी। भागलपुर में बहने वाली इस नदी पर सरकार ने लोहे का पुल बनवाया तो नामकरण किया गया-चंपा नाला ब्रिज। पौराणिक नदी को बचाने के लिए दैनिक जागरण ने छेड़ा है अभियान। (पेज-10)

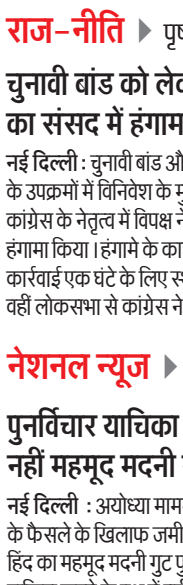

जागरण विशेष

पद्मश्री भारत भूषण बता रहे कैसे करें किसानी...

हापुड़ : उन्नत कृषि के लिए वर्ष 2019 में पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के निवासी भारत भूषण त्यागी ने विकसित की है जैविक कृषि की कारगर पद्धति। वह लोगों को इस खेती के प्रति जागरूक करने में जुटे हैं। (पेज-10)

महाराष्ट्र में शिवसेना संग सरकार बनाने को तैयार कांग्रेस

असमंजस खत्म ▶ सरकार गठन पर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में पार्टी की कार्यसमिति में बनी सहमति

कांग्रेस-राकांपा ने तैयार किया प्रारूप, शुक्रवार को शिवसेना से चर्चा के बाद एलान संभव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

महाराष्ट्र में सरकार गठन पर जारी असमंजस पूरी तरह खत्म हो गया है। शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने पर कांग्रेस कांग्रेस कार्यसमिति ने मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि शुक्रवार को महाराष्ट्र में कांग्रेस, राकांपा व शिवसेना नेताओं के बीच बैठक होगी और उसके बाद सरकार गठन की घोषणा कर दी जाएगी। कोशिश है कि नवंबर में ही नई सरकार का शपथ ग्रहण हो जाए।

महाराष्ट्र में शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस सरकार गठन में सबसे बड़ा असमंजस कांग्रेस के अंदर ही था। दरअसल वह कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा वाली शिवसेना के साथ जाने में असहज थी। पार्टी के अंदर ही अलग-अलग सुर थे। एक सप्ताह से ज्यादा चले बैठकों के दौर में तीनों दलों के बीच यह सहमति बन गई है कि हर किसी को कुछ समझौता करना ही होगा। वर्तमान सियासी माहौल में सब महसूस कर रहे हैं कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में सत्ता में वापसी जरूरी है।

महाराष्ट्र में सरकार गठन के मसले पर गुरुवार को भी नई दिल्ली में राकांपा प्रमुख शरद पवार के आवास पर कांग्रेस और राकांपा नेताओं की बैठक हुई। प्रेट्र

यूं तो बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कांग्रेस प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेताओं के बीच बैठक के बाद ही सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया था। गुरुवार को सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में सरकार बनाने को सैद्धांतिक रूप से हरी झंडी दे दी गई।

उसके बाद दिल्ली में शरद पवार के आवास पर कांग्रेस के अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश तथा राकांपा की सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार समेत दूसरे नेताओं की बैठक हुई और प्रारूप पर चर्चा हुई। शुक्रवार को मुंबई में राकांपा, कांग्रेस और शिवसेना की बैठक हो सकती है। संभव है कि उसके बाद सरकार बनाने की घोषणा हो जाए। शिवसेना को भी अनौपचारिक रूप से प्रारूप के बारे में जानकारी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि तीनों दलों की ओर से राज्यपाल को अलग-अलग पत्र देकर जानकारी दी जाएगी कि वे साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं।

ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री : अभी कांग्रेस और राकांपा नेताओं की ओर से सरकार के प्रारूप पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि सीएम पद पर 50:50 फार्मूला लागू होगा। यानी पहले ढाई साल शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा और बाकी के ढाई साल राकांपा का। उपमुख्यमंत्री पद पूरे पांच साल कांग्रेस के पास रहेगा। मंत्री पद में संख्या बल के हिसाब से हिस्सेदारी होगी और अहम मंत्रालयों में भी तीनों दलों का प्रतिनिधित्व होगा। सरकार के लिए साझा कार्यक्रम तैयार होगा और समन्वय के लिए भी व्यवस्था तैयार की जा सकती है, ताकि विवाद की स्थिति न खड़ी हो।

कांग्रेस को महाराष्ट्र में दफन कर देगा यह गठबंधन : निरूपम

मुंबई, प्रेट्र : कांग्रेस नेता संजय निरूपम ने शिवसेना के साथ जाने के फैसले को पार्टी के लिए घातक बताया है। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस ने कई साल पहले उत्तर प्रदेश में बसपा से गठबंधन करके गलती की थी। पार्टी आज तक वहां इससे उबर नहीं पाई है। हम वही गलती महाराष्ट्र में कर रहे हैं। शिवसेना सरकार में तीसरे नंबर की पार्टी बनना कांग्रेस के दफन हो जाने जैसा है। बेहतर होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष किसी दबाव में नहीं आएं।' इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि कांग्रेस को तब तक सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए, जब तक उसे भी मुख्यमंत्री पद न मिल जाए। आठवले ने कहा, कांग्रेस को दो साल शिवसेना और डेढ़-डेढ़ साल कांग्रेस-राकांपा के मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखना चाहिए।

> राकांपा और कांग्रेस के बीच सभी मुद्दों पर सहमति है। गठबंधन के प्रारूप पर शुक्रवार को फैसला होगा। अंतिम एलान मुंबई में होगा।
>
> -पी. चव्हाण (कांग्रेस नेता)

'विधायक खरीद की कोशिश हुई तो सिर फोड़ देंगे'

शिवसेना के विधायक अब्दुल सत्तार ने भाजपा को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, 'भाजपा किसी भी विधायक की खरीद-फरोख्त नहीं कर पाएगी। जो भी विधायकों की खरीद-फरोख्त की कोशिश करेंगे, उनके सिर फोड़ दिए जाएंगे। हम अस्पताल में उनके इलाज की व्यवस्था भी करेंगे।'

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

चुनावी बांड को लेकर कांग्रेस का संसद में हंगामा

नई दिल्ली : चुनावी बांड और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के मुद्दे पर गुरुवार को कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने संसद में जमकर हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई एक घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं लोकसभा से कांग्रेस ने वाकआउट किया।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 5

पुनर्विचार याचिका के पक्ष में नहीं महमूद मदनी गुट

नई दिल्ली : अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद का महमूद मदनी गुट पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के पक्ष में नहीं है। गुट ने इसे अहितकर बताया है और याचिका की वकालत करने वालों को नुकसान होने की आशंका से सचेत भी किया है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

रणनीतिक विनिवेश की सूची में शामिल हैं 30 और कंपनियां

नई दिल्ली : बीपीसीएल, एससीआइ और कानकॉर की रणनीतिक बिक्री के जरिये केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय कंपनियों की थाह लेने की कोशिश कर रही है। अगर यह बिक्री सफल रही तो संभव है कि 2020-21 और 21-22 में 30 अन्य कंपनियों का भी विनिवेश हो जाए।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

राष्ट्रपति गोतबाया ने बड़े भाई को दिलाई पीएम पद की शपथ

कोलंबो : श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने गुरुवार को अपने बड़े भाई महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। इस द्वीपीय देश में पहले भी ऐसा हो चुका है, जब गोतबया और महिंदा एक साथ अहम पदों पर रहे।

टेस्ट की जंग

दूसरा टेस्ट	दोपहर 1:00 बजे से
भारत vs बांग्लादेश	स्थान : कोलकाता
	प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधों से जुड़े हर सवाल का देना होगा जवाब : सुप्रीम कोर्ट

- याचिकाकर्ताओं ने विस्तार से बात रखी है, प्रशासन को उन्हें संतुष्ट करना होगा
- केंद्र ने कहा, एहतियात के तौर पर लगाए गए थे प्रतिबंध

नई दिल्ली, एजेंसियां : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन से कहा कि उसे पूर्ववर्ती राज्य से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में हर सवाल का जवाब देना होगा। न्यायमूर्ति एनवी रमना के नेतृत्व वाली पीठ ने प्रशासन की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि याचिकाकर्ताओं ने विस्तार से अपनी बात रखी है। 'मिस्टर मेहता, आपको याचिकाकर्ताओं के हर सवाल का जवाब देना होगा। आपके जवाबी हलफनामे से हमें किसी नतीजे पर पहुंचने में कोई मदद नहीं मिली है। यह संदेश न दें कि आप इस मामले पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं।' मेहता ने कहा, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिबंधों पर जो भी बात कही है, वह ज्यादातर 'गलत' है और अदालत में बहस के दौरान वह हर बात का हर पहलू से जवाब देंगे।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा, उनके पास मामले की स्थिति रिपोर्ट है, लेकिन उन्होंने अभी वह अदालत में दाखिल नहीं की है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर में रोज हालात बदल रहे हैं। रिपोर्ट दाखिल करने के समय वह एकदम वास्तविक हालात का ब्योरा देना चाहते हैं। इस बीच, प्रतिबंधों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि इनके चलते न तो एक भी आदमी मारा गया न ही गोली चलाने की नौबत आई। केंद्र सरकार से इन प्रतिबंधों पर सवाल पूछे जाने के बजाय उसे पांच अगस्त के ऐतिहासिक फैसले के बाद स्थितियों से शानदार तरीके से निपटने के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

वेणुगोपाल ने कहा कि पांच अगस्त के बाद यदि इंटरनेट सेवा बहाल रहती, तो एक क्लिक में दसियों हजार संदेश अलगाववादियों और आतंकियों तक पहुंचते। इसका नतीजा होता कि व्यापक अराजकता फैल जाती और बड़ी हिंसक घटनाएं होतीं।

कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान वेणुगोपाल ने कहा कि हाल की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने यह एहतियाती कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2016 में बुरहान वानी समेत तीन आतंकी मारे गए थे। उस समय तीन महीने के लिए जब राज्य में प्रतिबंध लगाया गया, तो किसी ने मुकदमा नहीं किया। और इस बार प्रतिबंधों के खिलाफ 20 याचिकाएं दायर कर दी गईं।

वेणुगोपाल ने कहा कि भारत सरकार ने जिस तरह घटनाओं को संभाला, उसके लिए उसकी तारीफ की जानी चाहिए। कश्मीर घाटी में हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से सीमापार से आतंकियों की घुसपैठ कराई जा रही थी। स्थानीय आतंकियों और अलगाववादियों ने आम नागरिकों को बंधक बना लिया था। ऐसे में यदि सरकार ने एहतियाती कदम नहीं उठाया होता, तो यह उसकी मूर्खता होती। वेणुगोपाल ने कहा कि अनुच्छेद 370 से आतंकियों और हुर्रियत कान्फ्रेंस को शह मिलती थी। इसे खत्म करने के बाद यदि बड़ा एहतियाती कदम नहीं उठाया जाता, तो बड़े पैमाने पर अराजकता फैल सकती थी।

बीजिंग ने 15 साल में प्रदूषण से मुक्ति पाई हम उससे पहले कर दिखाएंगे : जावडेकर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- दिल्ली सहित देश के बड़े हिस्से की बिगड़ी आबोहवा पर संसद ने जताई चिंता
- चर्चा के बहाने राजनीति करने वालों पर केंद्रीय मंत्री ने साधा निशाना

दिल्ली-एनसीआर सहित देश के बड़े हिस्से की बिगड़ी आबोहवा को लेकर गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में जोरदार चर्चा हुई। सांसदों ने बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर चिंता जताई और इससे निपटने के लिए सरकार को काफी सुझाव भी दिए। हालांकि राज्यसभा में चर्चा के जवाब में सरकार ने इससे जल्द निपटने का भरोसा दिया। साथ ही कहा, बीजिंग ने ऐसे ही प्रदूषण से निपटने में 15 साल लगाए थे, लेकिन हम इससे पहले ही वायु प्रदूषण की समस्या से पार पा लेंगे। सरकार ने इसे लेकर गंभीर और जिम्मेदार पहल शुरू की है। इसका असर यह रहा कि पिछले तीन साल में इसमें सुधार भी दिखा है।

खास बात यह है कि राज्यसभा में गुरुवार को शुरू हुई अल्पकालिक चर्चा जहां कुछ घंटों में समाप्त हो गई, वहीं लोकसभा में यह चर्चा अभी भी जारी है। चर्चा की शुरुआत मंगलवार को कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने की थी। हालांकि यह बुधवार को लोकसभा की कार्यसूची में दूसरे विषयों के दर्ज होने के चलते नहीं हो पाई थी। जो गुरुवार को फिर शुरू हुई और शून्यकाल के बाद देर शाम तक चली। इस दौरान चर्चा में सभी दलों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि शुक्रवार को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री इस पर अपना जवाब देंगे।

राज्यसभा में गुरुवार को वायु प्रदूषण की समस्या पर बोलते केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर। प्रेट्र

इस बीच, राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए जावडेकर ने कहा कि वायु प्रदूषण कोई राजनीतिक विषय नहीं है, इसलिए सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर मिल-जुलकर इससे निपटने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए कहा कि कुछ लोगों ने इस मामले को जिस तरीके से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की, वह दुखद है।

जावडेकर ने कहा कि प्रदूषण से निपटने को दिल्ली-एनसीआर सहित देश के 122 शहरों को लेकर एक कार्ययोजना (नेशनल एक्शनप्लान फॉर क्लीन एयर) बनाई गई है। इसके तहत सभी को पैसा दिया गया है। साथ ही सभी शहरों से अपनी भौगोलिक और मौजूदा परिस्थितियों के लिहाज से योजना तैयार करने को कहा गया है। यह मुद्दा वैसे भी किसी दूसरे पर छोड़ने का नहीं है, खुद करने का है। उन्होंने कहा कि चर्चा में ज्यादातर सदस्यों ने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की बात कही है, तो मैं बताना चाहता हूं कि भारत और चीन दुनिया के दो ऐसे देश हैं जिनका ग्रीन कवर पिछले वर्षों में बढ़ा है। उन्होंने इस दौरान दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में लगातार हो रहे सुधार का भी जिक्र किया और कहा कि पहले की तुलना में अब अच्छी हवा वाले दिनों की संख्या बढ़ी है। दोनों ही सदनों में चर्चा के दौरान सभी दलों के सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया।

किसी ने यज्ञ कराने, किसी ने क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित करने का दिया सुझाव पेज>>3

व्यापम की सिपाही भर्ती परीक्षा में सभी 31 आरोपित दोषी करार

नईदुनिया, भोपाल

- सीबीआइ की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला, 25 को सुनाई जाएगी सजा

मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा 2013 में सभी 31 आरोपितों (उत्तर प्रदेश के 14, मध्य प्रदेश के 17) को भोपाल की विशेष सीबीआइ अदालत ने धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का दोषी पाया है। सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। 25 तारीख को सजा सुनाई जाएगी। मामले की सुनवाई सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसबी साहू की कोर्ट में हुई।

व्यापम द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा की जांच एसटीएफ कर रही थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह मामला दिसंबर 2015 में सीबीआइ को ट्रांसफर कर दिया गया था। सीबीआइ ने जांच के आधार पर भोपाल की विशेष अदालत में अप्रैल 2017 में चालान पेश किया था। जिनके खिलाफ चालान पेश किया गया था, उनमें 12 अभ्यर्थी, उनके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाले 12 फर्जी उम्मीदवार तथा दलाल शामिल थे। सीबीआइ ने इनके खिलाफ फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।

ऐसे किया था फर्जीवाड़ा : पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले दलालों ने असली अभ्यर्थियों से संपर्क किया था और कहा था कि उनके स्थान पर वे फर्जी उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल कराएंगे, जिससे उनका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। इसके एवज में असली अभ्यर्थियों से दो लाख रुपये तक की राशि ली गई। परीक्षा देने के एवज में फर्जी अभ्यर्थियों को 50 हजार रुपये तक दिए गए। इसके लिए फर्जी तरीके से प्रवेश पत्र तक तैयार किए गए थे।

आज से दिखेगा गुलाबी गेंद का कमाल

अभिषेक त्रिपाठी, कोलकाता

- ईडन गार्डेंस में भारत-बांग्लादेश के बीच डे-नाइट टेस्ट मैच आज से

कई वर्षों की ना-नुकुर और डर के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब भारतीय टीम गुलाबी गेंद से डे-नाइट टेस्ट मैच खेलने जा रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डेंस स्टेडियम में शुक्रवार से यह मैच खेला जाएगा। दोनों ही टीमों का यह पहला डे-नाइट टेस्ट और इस सीरीज का दूसरा मैच होगा। भारत में पहली बार गुलाबी गेंद से टेस्ट खेला जा रहा है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का यह 12वां डे-नाइट टेस्ट मैच होगा। भारत और बांग्लादेश को छोड़कर आठ प्रमुख टीमें पहले ही डे-नाइट टेस्ट मैच खेल चुकी हैं। नए टेस्ट देश अफगानिस्तान और आयरलैंड ने भी अभी कोई डे-नाइट टेस्ट नहीं खेला है।

देश में पहली बार किसी टेस्ट मैच में गुलाबी गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले भारत में सभी टेस्ट मैच लाल गेंद से खेले गए थे। पारंपरिक टेस्ट मैच की तरह डे-नाइट टेस्ट में भी प्रतिदिन तीन सत्र का खेल खेला जाएगा, लेकिन यह सुबह नौ-साढ़े नौ बजे की जगह दोपहर एक बजे शुरू होगा। इस मैच में भी विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। भारत ने इस सीरीज के पहले मुकाबले में इंदौर में बांग्लादेश को पारी और 130 रनों से हराया था। (पेज-14 भी देखें)

स्टेडियम में अभ्यास के दौरान गेंद को लेकर बात करते रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा। प्रेट्र

इस मैच के लिए विशेष इंतजाम

- टॉस दोपहर 12.30 पर होगा और पहले सत्र की शुरुआत 1.00 बजे होगी
- गावस्कर, तेंदुलकर, कपिल देव सहित कई महान क्रिकेटर यहां उपस्थित होंगे
- सौरव गांगुली के साथ ही राहुल द्रविड़ व अनिल कुंबले भी आएंगे
- चायकाल में पूर्व कप्तान विशेष गाड़ियों से स्टेडियम में चक्कर लगाएंगे
- पहले दिन संगीत कार्यक्रम भी होंगे और दिन के अंत में सम्मान समारोह होगा
- बांग्लादेश की गायक रूना लैला, बंगाल के गायक जीत गांगुली परफॉर्म करेंगे
- इस मैच को देखने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी मौजूद रहेंगी
- बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस दौरान उनके साथ रहेंगी

उप्र में जबरन धर्मांतरण पर रोक का बनेगा नया कानून

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : जबरन धर्मांतरण की घटनाओं पर रोक के लिए उत्तर प्रदेश में जल्द ही नया कानून लागू किया जा सकता है। राज्य विधि आयोग ने 'उप्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल-2019' के नाम से बनाया गया मसौदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा है।

विधि आयोग की सचिव सपना त्रिपाठी द्वारा एक एजेंसी को दी गई जानकारी के मुताबिक, जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिए नए कानून का मसौदा मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। यह रिपोर्ट देश की आजादी से पहले और बाद के कानून के साथ ही पड़ोसी देश नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान के कानून का परीक्षण करते हुए तैयार की गई है। विधि आयोग का मत है कि जबरन धर्मांतरण जैसी घटनाओं पर रोक के लिए प्रदेश का मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरह यहां भी विशेष कानून बनाने की जरूरत है।

व्यवस्था में बदलाव

पहली दिसंबर तक मुफ्त में लें फास्टैग, वरना लगेगा दोगुना टोल टैक्स

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बोले, अभी एनएच के 537 में से 520 प्लाजा पर फास्टैग टोल टैक्स कलेक्शन के इंतजाम, स्टेट हाईवे को भी फास्टैग प्रणाली के अंतर्गत लाने के प्रयास जारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

यदि आप पहली दिसंबर तक एनएचएआइ के प्वाइंट ऑफ सेल से फास्टैग खरीदेंगे तो ये आपको मुफ्त में मिलेगा। आपसे इसका मूल्य और सेक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ली जाएगी। आपको केवल फास्टैग को रिचार्ज कराना होगा, ताकि जब आप किसी नेशनल हाईवे पर निकलें तो टोल टैक्स इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अदा हो जाए और आप बेरोकटोक आगे बढ़ जाएं। लेकिन यदि आप इसके बिना फास्टैग लेन में प्रवेश कर गए तो आपको कैश के तौर पर दोगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि कैश लेन से जाने वाले वाहन निर्धारित टोल टैक्स देकर जा सकेंगे, लेकिन उन्हें कतार में लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि पहली दिसंबर से देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग को अनिवार्य किया जा रहा है। अभी तक एनएच के 537 टोल प्लाजा में से 520 प्लाजा पर फास्टैग लायक इलेक्ट्रॉनिक टोल टैक्स कलेक्शन के इंतजाम किए जा चुके हैं। मैन्युअल टोल कलेक्शन वाले 17 टोल प्लाजा में भी शीघ्र ही फास्टैग व्यवस्था लागू करने के इंतजाम किए जा रहे हैं।

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) प्रोग्राम के तहत शीघ्र ही प्रादेशिक राजमार्गों अथवा स्टेट हाइवे पर भी फास्टैग की स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए एनएचएआइ विभिन्न राज्य सरकारों के साथ अनुबंध कर रहा है। अभी तक उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र समेत आठ राज्यों के साथ अनुबंध किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में स्टेट हाईवे के 13 टोल प्लाजा पर फास्टैग स्वीकार किए जाने लगे हैं। देशभर में 2014 से अब तक 66 लाख फास्टैग की बिक्री हो चुकी है। ट्रांसपोर्ट सेग्मेंट के 90 फीसद वाहनों में फास्टैग लग चुके हैं। नवनिर्मित वाहनों में 2017 से फास्टैग लगकर आ रहा है। केवल कारों, दोपहिया और तिपहिया सवारी वाहनों में फास्टैग अपनाए जाने की रफ्तार सुस्त है। (पेज-12 भी देखें)

लोकसभा में गुरुवार को चर्चा में हिस्सा लेते केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। प्रेट्र

राज्यों के साथ बैठक जल्द

गडकरी ने कहा कि महानगरों को जाम और प्रदूषण से मुक्त करने के लिए रिंग रोड बनाने की योजना के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों से 50 प्रतिशत खर्च स्वयं वहन करने को कहा था। लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए हमने उन्हें दूसरे तरीकों से सहयोग करने को कहा है। इसके तहत वे मुफ्त जमीन समेत कई गतिविधियों के लिए टैक्स में छूट देकर मदद कर सकते हैं।

रोड-साइड सुविधाएं

हाईवे के किनारे स्थापित होने वाली इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं (पेट्रोल पंप, होटल-मोटल, पार्किंग प्लाजा, हेलीपैड आदि) में निवेश की नीति में भी कुछ बदलाव किया गया है। अब लंदन की तर्ज पर टोल प्लाजा के ऊपर रेस्टोरेंट बनेंगे। इटालियन स्टाइल पार्किंग प्लाजा का निर्माण एनएचएआइ और एनएचआइडीसीएल करेंगी। इन दोनों को राज्यों में 50 पार्किंग प्लाजा के निर्माण के आर्डर भी मिले हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की माली हालत दुरुस्त है

गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) की वित्तीय स्थिति दुरुस्त है। अगले दो-तीन साल में उसे सालाना 30 हजार करोड़ का टोल हासिल होने लगेगा। हमारा इरादा एनएचएआइ की आमदनी को बढ़ाकर सालाना एक लाख करोड़ रुपये करने का है। बुधवार को कैबिनेट ने टीओटी मॉडल के तहत बन चुके राजमार्गों के मौद्रीकरण के नियमों में ढील देकर एक से दो साल पहले बन चुकी सड़कों के भी मौद्रीकरण की इजाजत दे दी है।

प्रियंका के फैसलों से असंतुष्ट उप्र के वरिष्ठ कांग्रेसियों को नोटिस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के फैसलों पर असंतोष जताकर बदलाव की उम्मीद संजो रहे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसियों को झटका लगा है। प्रियंका की त्योरियां चढ़ने पर प्रदेश की अनुशासन समिति ने दो बैठकों में शामिल हुए ग्यारह वरिष्ठ नेताओं को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

संगठन में सिर्फ युवाओं को ही तरजीह दिए जाने के प्रियंका के निर्णय से वे कांग्रेसी खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जो पिछले कई दशकों से पार्टी में काम कर रहे हैं। इनमें पूर्व जनप्रतिनिधि, पूर्व पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। इन लोगों ने पिछले दिनों दो बैठकें कर अपना दर्द बयां किया और तय किया कि इस मुद्दे पर वे सोनिया गांधी से मुलाकात कर बताएंगे कि कैसे ये फैसले पार्टी के हित में नहीं हैं। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी नाराजगी को गंभीरता से लेकर हाईकमान शायद निर्णय में कुछ बदलाव करे। बुधवार को हुई पूर्व विधायक व पूर्व प्रत्याशियों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आश्वस्त भी किया था कि सभी वरिष्ठजनों को सम्मान होगा। इसी बीच गुरुवार को प्रियंका और अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर अनुशासन समिति के सदस्य अजय राय ने इन पुराने कांग्रेसियों को अनुशासनहीनता पर नोटिस जारी कर दिए। इन सभी से 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

प्रियंका गांधी वाड्रा (फाइल)

दो बैठकें कर अपनी उपेक्षा पर बयां किया था दर्द

इन्हें दिए गए नोटिस : पूर्व सांसद संतोष सिंह, पूर्व एमएलसी सिराज मेंहदी, पूर्व मंत्री रामकृष्ण द्विवेदी, सत्यदेव त्रिपाठी, एआइसीसी सदस्य राजेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्र, हाफिज मोहम्मद उमर, विनोद चौधरी, नेक चंद्र पांडेय, युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वयंप्रकाश गोस्वामी।